भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 505
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में मेट्रो रेल नेटवर्क

505. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की तमिलनाडु में, विशेष रूप से चेन्नई और कोयम्बटूर जैसे शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु में प्रस्तावित मेट्रो लाइन विस्तार का ब्यौरा क्या है और इसकी समय-सीमा और इसमें सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राज्य में मेट्रो लाइनों के विस्तार के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया गया है;

(घ) क्या सरकार को इन मेट्रो लाइन के विस्तार संबंधी कार्यान्वयन में किसी चुनौती या देरी का सामना करना पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ) शहरी परिवहन राज्य का विषय है, जो शहरी विकास का अभिन्न अंग है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) मेट्रो रेल परियोजनाओं सहित शहरी परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजना बनाने और शुरू करने के लिए जिम्मेदार है। चेन्नई में चरण -1 और चरण -1 विस्तार परियोजना के तहत 54 किमी मेट्रो नेटवर्क पहले से ही चालू है। केंद्र सरकार द्वारा 118.9 किलोमीटर की चेन्नई चरण-2 परियोजना को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल), जो चेन्नई चरण-2 परियोजना के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन तंत्र है, ने चरण-2 परियोजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति को क्रमशः 40.41% और 32.74% सूचित की है। तमिलनाडु सरकार ने कोयंबटूर मेट्रो रेल परियोजना का डीपीआर अग्रेषित किया है। हालांकि, तमिलनाडु सरकार द्वारा चेन्नई,

कोयंबटूर या किसी अन्य शहर में मेट्रो परियोजना के विस्तार का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेट्रो परियोजना लागत गहन होने के कारण केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर इनके व्यापक मूल्यांकन और जांच की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य सरकार (यूटी) द्वारा प्राप्त प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरों या शहरी समूहों में ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करती है।

******